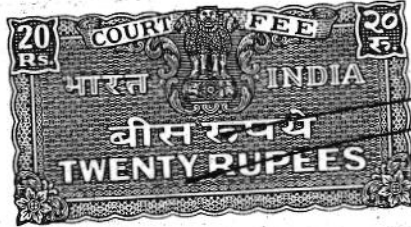


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प रीवा) म0प्र0



RS. 20/-

R-3067-III-114

मुनि प्रसाद कुशवाहा पिता स्व0 श्री विश्राम कुशवाहा निवासी ग्राम चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

निगरानीकर्ता

बनाम

राजमणि कुशवाहा पिता श्री रामाधार कुशवाहा निवासी ग्राम चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 24.06.2014 प्र.क. 105/अ-66/2014-14 द्वारा पारित अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 अन्तर्गत धारा 7 म0प्र0 वास स्थान दखल कार (भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1980 ई0

434
5-8-14

श्री. निरंजन काठक एड के द्वारा आज दिनांक 5-8-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2749
रेजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
मान्यवर को प्राप्त
25-8-14

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

राजस्व मण्डल ग्वालियर यह कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 24.06.2014 प्र0क0 105/A66/2013-14 अधिकारित रहित विधि व प्रकिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2.) यह कि निगरानीकर्ता भूमिहीन एवं अत्यन्त गरीब व्यक्ति है जिसका पुराना पैतृक माकान अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 382/5 रकवा 0.113 हे0 के अंश भाग 0.018 हे0 यानी साढे चार ढि0 स्थित मौजा चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 पर बना हुआ है जिस पर निगरानीकर्ता स परिवार निवास व निस्तार अर्सा पूर्व कई वर्ष से करता चला आ रहा है इसी भूखण्ड का पट्टा एवं भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने वावत

Handwritten signature and date at the bottom right corner.

59

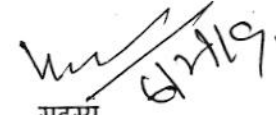
मुनि / राजमणि

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक निगः 3067-III/14

जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों के हस्ताक्षर
06/8/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक 18/12/2018 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 105/अ-66/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24/6/2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 29/4/2019 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">भौकृत</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	